



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262111  
CG-DL-E-30032025-262111

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1439]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/ चैत्र 5, 1947

No. 1439]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/ CHAITRA 5, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

का.आ. 1457(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1868(अ) द्वारा, तारीख 9 जून, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1868(अ), तारीख 9 जून, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1868(अ), तारीख 9 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखें जाएंगे, अर्थात्:-

**“5. मानीटरी समिति.** – केन्द्रीय सरकार एक मानीटरी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

- |   |                     |
|---|---------------------|
| (i) जिला कलेक्टर, नेल्लोर   | - अध्यक्ष, पदेन;    |
| (ii) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामित किया जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि | - सदस्य;            |
| (iii) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ                   | - सदस्य;            |
| (iv) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य-सचिव  | - सदस्य, पदेन;      |
| (v) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुडूर  | - सदस्य, पदेन;      |
| (vi) प्रभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबंधन प्रभाग, सुल्लुरपेट  | - सदस्य, पदेन;      |
| (vii) उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), नेल्लोर  | - सदस्य सचिव, पदेन। |

(2) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में सम्मिलित हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

- (3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास निर्दिष्ट जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
- (5) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।
- (7) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी है, जैसा वह ठीक समझे।”

[फा.सं.25/59/2014-ईएसजेड/आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा , वैज्ञानिक “जी”

**टिप्पण.-** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 9 जून, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1868(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26<sup>th</sup> March ,2025

**S.O. 1457(E).**—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Nelapattu Bird Sanctuary, Andhra Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1868(E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1868(E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1868(E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2017; namely: -

In the said notification, for paragraphs 5, the following paragraph shall be substituted, namely: -

“5. **Monitoring Committee.** - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, consisting of the following persons, namely :-

- (i) District Collector, Nellore – Chairman, *ex officio*;
- (ii) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh from time to time every three years– Member;
- (iii) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh from time to time every three years – Member;
- (iv) Member-Secretary of the State Biodiversity Board– Member, *ex officio*;
- (v) Regional Officer, State Pollution Control Board, Gudur– Member, *ex officio*;
- (vi) Divisional Forest Officer, Wildlife Management Division, Sullurpet- Member, *ex officio*;
- (vii) Deputy Conservator of Forests (Territorial), Nellore – Member Secretary, *ex officio*.

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department, representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31<sup>st</sup> March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30<sup>th</sup> June of that year in pro-forma specified in **Annexure-IV**.

- (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”

[F. No. 25/59/2014-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA , Scientist “G”

**Note.-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1868(E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2017.